चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर गिरकर 4.8 प्रतिशत के स्तर पर

तीन प्रमुख क्षेत्रों- कृषि, विनिर्माण और खनन के निराशाजनक प्रदर्शन की वजह से देश की सकल घरेलू उत्पाद विकास दर चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में गिरकर 4.8 प्रतिशत तक पहुंच गई। इस कारण 2012-13 के वित्त वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत विकास दर दर्ज की गई जो इस दशक में न्यूनतम है।

2012-13 की पहली तिमाही में 5.4 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 5.2 प्रतिशत की विकास दर के बाद चौथी तिमाही की 4.8 प्रतिशत की दर तीसरी तिमाही की 4.7 प्रतिशत के मुकाबले मामूली तौर पर अधिक है लेकिन 2011-12 के जनवरी-मार्च तिमाही की 5.1 प्रतिशत की दर से काफी कम है जब समूचे वित्त वर्ष की सकल घरेलू उत्पाद दर 6.2 प्रतिशत दर्ज की गई।

सकारात्मक संकेत

प्रमुख क्षेत्रों के लिए जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि अप्रैल में बुनियादी ढांचे के आठ क्षेत्रों में विकास दर गिरकर 2.3 प्रतिशत पर आ गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 5.7 प्रतिशत थी। ऐसे में राहत का संकेत केवल यही हो सकता है कि इस सप्ताह के शुरूआत में मौजूदा दीर्घ आर्थिक माहौल के विषय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर डी. सुब्बाराव द्वारा व्यक्त चिंताओं के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद में आई कमी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जून में दर कटौती की संभावनाएं बढ़ गई हैं इसके साथ ही नकद आरक्षी अनुपात को भी आसान करने की संभावना है।

यह रोचक है कि केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों से यह बात जाहिर होती है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2012-13 की जनवरी-मार्च की तिमाही में 2.6 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई जो कि पिछले राजकोषीय वर्ष की इसी अवधि के दौरान महज 0.1 प्रतिशत थी। हालांकि 2011-12 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले पिछले पूरे राजकोषीय वर्ष के दौरान इस क्षेत्र को केवल एक प्रतिशत का विस्तार मिला।

इसके साथ ही 2012-13 की जनवरी-मार्च की तिमाही के दौरान खनन और उत्खनन क्षेत्र में 3.1 प्रतिशत की कमी आई जबकि 2011-12 की इसी अवधि के दौरान यह 5.2 प्रतिशत थी। इस क्षेत्र में दोनों वर्षों के लिए कमी की दर 0.6 प्रतिशत बनी रही।

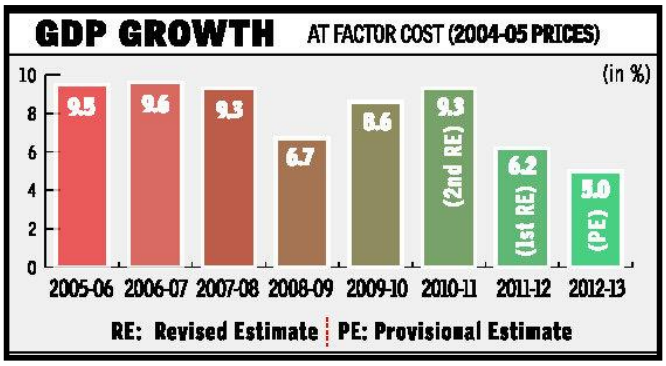

कृषि क्षेत्र

चौथी तिमाही में मात्र 1.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा । जबकि 2011-12 की इसी अवधि के दौरान यह दर 2 प्रतिशत थी। समूचे वर्ष के लिए भी कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 2011-12 के 3.6 प्रतिशत के मुकाबले केवल 1.9 प्रतिशत रही।

वित्त मंत्री श्री पी. चिंदबरम ने कहा कि "वृद्धि दर के आंकड़े अपेक्षाओं के अनुकूल हैं।" योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का मानना है कि अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने के संकेत मिले हैं लेकिन इसके मजबूती से वापसी के नहीं। उन्होंने कहा कि "इस बात के सबूत हैं कि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। लेकिन हमारे पास अब भी इसके वापस पटरी पर लौटने के संकेत नहीं हैं। पिछली तिमाही में 4.8 प्रतिशत की दर के बाद 6 प्रतिशत (विकास) प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण है।"

प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सी. रंगराजन ने भी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों को संभावना के अनुकूल बताया है और दर में कटौती की आशा जताई है । उन्होंने कहा कि " जीडीपी के यह आंकड़ें संभावित थे.....जहां तक विनिर्माण का संबंध है , तो शायद हम न्यूनतम स्तर तक पहुंच गए हैं। थोक बिक्री मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति में कमी आई है। मुझे लगता है कि आरबीआई द्वारा ठोस कदम उठाने के लिए काफी वजह हैं।"

(स्रोतः द हिन्दू)